प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साहित्य का अध्ययन

डॉ. विष्णु भगवान, प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग,चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
हेमंत शर्मा, शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा।

सारांश

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की समीक्षा इस तरह की गई है कि यह योजना छोटे कारोबारियों और पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए फ़ायदेमंद रही है। इस योजना से उद्यमशीलता गतिविधियां बढ़ी हैं और इन कारोबारियों को वित्तीय सहायता मिली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्यमियों, व्यापारियों और श्रमिकों को सस्ती और आसान ऋण सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे अपना व्यापार शुरू कर सकें या उसे बढ़ा सकें। यह योजना 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत तीन प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं, शिशु श्रेणी के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण एवं किशोर श्रेणी के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण औरतरुण श्रेणी में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया करवाया जाता है। यह योजना बिना किसी संपार्श्विक(collateral) के ऋण देती है, जिससे छोटे व्यापारी और उद्यमी आसानी से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।

साहित्य का अध्ययन:

दीक्षित व मुनमुन घोष राधिका (2013)[1] के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन सबसे परेशान करने वाला तथ्य क्या है? इसकी वृद्धि के बारे में यह है कि इसकी वृद्धि न केवल असमान रही है बल्कि असतत भी रही है। इस अर्थ में यह असमान रहा है, इसके विकास प्रदर्शन में कोई एकरूपता नहीं रही है और यह विकास के संबंध में अलग रहा है।अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में विकास लाभों का वितरण भी अलग रहा है। इस प्रकार भारतीय आर्थिक विकास में समावेशी विकास की आवश्यकता सामने आती है। हालाँकि समावेशी विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, और संसाधन सृजन और गतिशीलता के लिए वित्तीय समावेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, साक्षरता दर, बेरोजगारी दर और वित्तीय समावेशन सूचकांक जैसे मापदंडों पर विचार करना महत्वपूर्ण बताया गया है।

डॉ आर., रूपा, (2017)[2], के अनुसार माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम एक जीवंत, गतिशील और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े उद्योगों के साथ पूरक है। ये देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। एमएसएमई क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% योगदान देता है इसके अलावा कुल विनिर्माण उत्पादन में 45%, देश से निर्यात में 40% और 80 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस पृष्ठभूमि में एक ऐसे बैंक की आवश्यकता है जो विशेष रूप से सूक्ष्म इकाइयों का समर्थन शुरू किया गया और पेश किया गया जो उद्यमशीलता का समर्थन कर सकते हैं और इन इकाइयों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। मुद्रा 'वित्तविहीन लोगों को वित्तपोषित' करने का एक प्रयास है। माइक्रोफाइनेंस का उद्देश्य 'बैंक रहित लोगों को बैंक बनाना' है।

जॉर्ज और नलिनी (2018)[3] के निष्कर्षों के अनुसार, भारत में मध्यम और छोटे व्यवसायों को इस प्रकार इसे प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि यह आर्थिक विकास में योगदान दें । भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान छोटे उद्यमों को समर्थन देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लॉन्च किए। उन्होंने जांच की कि मुद्रा योजना भारत में सूक्ष्म, मध्यम और लघु व्यवसाय इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शुरू की गई योजना है। ऐसी योजनाएं कुशल श्रमिकों और शिक्षित युवाओं को उनके विकास के लिए प्रोत्साहित करने और समर्थन करने में मदद करती हैं। इसके अलावा व्यवसाय और आर्थिक विकास में योगदान करती हैं। छोटे व्यवसाय आर्थिक विकास की नींव बनाते हैं और इसे मजबूत करने की जरूरत है । पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में जो योजनाएं शुरू की गई हैं, वे सही दिशा में उठाये गये कदम है। यह माना जाता है कि मुद्रा बैंक जैसा बैंक बनाने से छोटी विनिर्माण इकाइयों और स्वयं को काफी फायदा होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 10 लाख रुपये तक की वित्तपोषण आवश्यकताओं वाले नियोजित व्यक्ति मुद्रा योजना के तहत लाभान्वित होंगे। भारत में लघु और सूक्ष्म व्यापार इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए यह सबसे किफायती योजना है। इस योजना के माध्यम से उद्यमियों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित होगा। यह योजना छोटे व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों की खुशहाली में इजाफा करेगी और बड़े पैमाने के उद्योग जोकि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की प्रगति में सकारात्मक योगदान देंगे। इस प्रकार कि योजनाओं से शिक्षित युवाओं को रोजगार और कुशल श्रमिकों का आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आने वाली पीढ़ी मेउद्यम, और मौजूदा छोटे व्यवसाय भी अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम होंगे। ठीक वैसे ही जैसे बैंकिंग के लिए मुद्रा बैंक का मुख्य उद्देश्य वित्त रहित लोगों को वित्त पोषित करना है।

रूपेश रोशन सिंह और अनीता बिंदल (2019)[4]के अनुसार भारत में छोटे पैमाने के व्यवसाय लोगों के जीवन का

स्रोत होते हैं। लोग संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों पर अपने ऋण के लिए निर्भर हैं, लेकिन अधिकांश व्यापार असंगठित क्षेत्र के ऋण पर ही आश्रित हैं। असंगठित क्षेत्र का ऋण बहुत अनियोजित होता है और गरीब लोगों को कर्ज में जाने की समस्या उत्पन्न कर रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए असंगठित क्षेत्र व्यवसायों का विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2015 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया, जिसे मुद्रा के रूप में जाना जाता है, छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वित्तीय सहायता और महत्वपूर्ण वित्तीय समावेश की महत्वपूर्ण योजनाएं प्रदान कर रही है। इस समावेशी योजना के तहत, कोई भी अपने व्यवसाय को आरंभ करने के लिए 10 लाखतक का ऋण ले सकता है। यह लेख हरियाणा राज्य में मुद्रा योजना के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए बैंकों द्वारा उपलब्ध उत्पादों पर भी। इसके अतिरिक्त, समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से प्राथमिकता क्षेत्र, के विकास के लिए व्यवसायों को बैंकों द्वारा प्रदान की गई योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

रोशन सिंह और अनीता बिंदल (2022)[5] भारत एक उच्च जनसंख्या वाला देश है। रोजगार प्रदान करना, भारतीय सरकार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत केवल तब टिक सकता है जब उसमें छोटे, मध्यम और सूक्ष्म उद्यम हों जो भारतीयों के लिए रोजगार बनाने के लिए हों। अधिकांश 20% जनसंख्या छोटे, सूक्ष्म, मध्यम उद्यमों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं। इसलिए, सरकार को छोटे व्यवसायों को ऋण सुविधाएं, प्रशिक्षण, विपणन सुविधाएं और उन्हें प्रकाशन की सुविधा प्रदान करके समर्थन प्रदान करना चाहिए। आज के व्यावसायिक वातावरण में छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को आर्थिक अशिक्षा, जानकारी की कमी, बुनियादी संरचना सुविधाओं की कमी, स्थापित करने का उच्च लागत के कारण अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल होता है। इन व्यवसायों का समर्थन करने के लिए भारतीय सरकार ने 2015 में MUDRA ऋण का आयोजन किया और बिना गिरवी के ऋण प्रदान किए। यह योजना गैर-कॉर्पोरेट छोटे व्यवसाय क्षेत्र में ऋण वितरण के लिए बहुत लाभदायक साबित हुई है। इसमें मुद्रा योजना पर प्रकाश डाला गया है।

शशांक बी. एस. और सुरेशरमणमय्या (2022)[6] के तहत गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अपंजीकृतउद्यमों के रूप में कार्य करता है। उन्हें ठीक से लेखा रखाव नहीं किया जाता है और वे आयकर क्षेत्रों के तहत आधिकारिक रूप से शामिल नहीं होते हैं। इसलिए, बैंकों को उन्हें ऋण देने में कठिनाई होती है। इस क्षेत्र का अधिकांश बाहरी वित्तीय स्रोतों का उपयोग नहीं करता है। भारत सरकार इस पृष्ठभूमि में एक माइक्रो इकाइयों विकास और पुनर्निधि एजेंसी (मुद्रा) बैंक की स्थापना कर रही है, एक कानूनी कार्यवाही के माध्यम से। यह एजेंसी सभी माइक्रो वित्त संस्थानों (एमएफआई) को विकास और पुनर्निधि करने के लिए जिम्मेदार होगी, जो निर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों में लगे छोटे / सूक्ष्म व्यापार इकाइयों को ऋण प्रदान करते हैं। बैंक स्थानिक / क्षेत्रीय स्तर के समन्वयकों के साथ साझेदारी करेगा ताकि छोटे / सूक्ष्म व्यापार उद्यमों के अंतिम मील वित्तियों को वित्त प्रदान किया जा सके। क्योंकि नियमन को कुछ समय लग सकता है, इसे एक स्वार्थी के रूप में सिडबी का एक इकाई के रूप में शुरू किया जाना प्रस्तावित है, ताकि सिडबी की पहलों और विशेषज्ञता से लाभ लिया जा सके।

अंजेश (2021)[7]के अनुसार माइक्रो इकाइयों में विभिन्न छोटे पैमाने की गतिविधियाँ होती हैं। इन इकाइयों को गैर-कॉर्पोरेट छोटे व्यवसाय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र को वित्तों की कमी, इक्विटी पूंजी की सीमित पहुंच, प्रौद्योगिकी की कमी और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बॉटलनेक है, जो संस्थागत वित्तीय समर्थन की कमी है। माइक्रोउद्यमियों के सामने आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार ने "मुद्रा" नामक योजना की शुरुआत की है। वर्तमान अनुसंधान का उद्देश्य PMMY योजना के लाभार्थियों में इसके बारे में विद्या, जागरूकता और जागरूकता के स्रोत का अध्ययन करना है। प्राथमिक डेटाशिवमोग्गा जिले के 50 मुद्रा योजना के लाभार्थियों से प्राप्त किया गया था, एक प्रश्नावली के माध्यम से और सेकेंडरीडेटा मुद्रा वेबसाइट से प्राप्त किया गया। डेटाएसपीएसएस द्वारा विश्लेषित किया गया था और सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग किया गया जैसे अधिकता, प्रतिशत और हाइपोथेसिस का परीक्षण करने के लिए टी-टेस्ट का उपयोग किया गया। अध्ययन का परिणाम यह था कि PMMY योजना के बारे में लाभार्थियों के बीच जागरूकता का कम स्तर है और 36% के लाभार्थियों के जागरूकता का स्रोत रिश्तेदार और दोस्तों से है।

योगेश महाजन (2019)[8] के अनुसार एक जनसंख्या के साथ एक अर्थव्यवस्था जैसे कि भारत को जीवित रखने के लिए, वहां प्रगतिशील छोटे, मध्यम और सूक्ष्म उद्यमों की आवश्यकता है जो बढ़ती हुई आबादी के लिए नौकरियों का सृजन करते हैं। आज छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग भारत में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इन एमएसएमईउद्यमों को ऋण, प्रशिक्षण, प्रकाशन और उनके उत्पादों का विपणन करने में सरकारी सहायता प्रदान की जाए। छोटे व्यवसायों या सूक्ष्म उद्यमों का मुख्य समस्याएं में जानकारी की कमी, वित्तीय अक्षरशाही, प्रवेश स्तर नीतियाँ, उच्च लागत, अवसर की कमी, अभाव बुनियादी संरचना, वित्तीय पहुंच की कमी और प्रौद्योगिकियों के बाधाओं शामिल हैं। भारत सरकार ने 2015 में मुद्रा ऋण प्रदान करके इन उद्यमों का समर्थन किया है जो बिना कोई गारंटी के ऋण देने के माध्यम से। यह योजना

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में सफल रही है। यह भी पाया गया कि मुद्रा ऋणों का अधिकांश 93% 50,000 रूपयेसे कम हैं। इस मुद्दे के प्रकाश में, महाराष्ट्र राज्य में पीएमएमवाई का अध्ययन और समीक्षा करना आवश्यक है। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में मुद्रा ऋणों की स्थिति को समझने का प्रयास करेगा। पाया गया है कि महाराष्ट्र राज्य में मुद्रा योजना में काफी सफलता हुई है, लेकिन सभी वर्गों के लोगों को वित्तीय समावेश के लिए और अधिक किया जाना चाहिए।

अजीत कुमार और पूनम रानी (2019)[9] के अनुसार विकासशील देशों के उद्यमियों में छोटे उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो अधिक बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। छोटे उद्योगों की स्थापना में मुद्रा की कमी होना मुख्य समस्या है। छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने अप्रैल 2015 में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) नामक एक योजना शुरू की। अनुवांशिक कुशल और विश्लेषणात्मक अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बैंकर्स कमेटी, हरियाणा से आवश्यक डेटा को एकत्र किया गया है। अध्ययन के परिणाम दिखाते हैं कि निजी बैंक शिशु श्रेणी के तहत अधिक ऋण प्रदान करते हैं जब उन्हें अन्य दो मुद्रा ऋणों के साथ तुलना की जाती है। इसका कारण यह है कि किशोर और तरुण श्रेणियों के तहत ऋण राशियां कहीं अधिक होती हैं, और इसलिए, निजी बैंकों के लिए जोखिमपूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमएमवाई के जिला-वार प्रदर्शन का विश्लेषण दर्शाता है कि शिशु श्रेणी के तहत, आधारभूत बड़े जिलों में सबसे अधिक लाभार्थियों और स्वीकृत राशि हैं। किशोर और तरुण श्रेणियों के लिए, सबसे शहरीकृत और गहरे आबादी वाले जिलों का सबसे अधिक हिस्सा है। लेकिन पीएमएमवाई के जिला-वार प्रदर्शन की गहराई का अंधकार यह है कि ग्रामीण और पिछड़े जिलों में हरियाणा में इन सभी श्रेणियों में कोई योगदान नहीं है। यह वास्तविक चिंता का विषय है और तत्काल ध्यान की आवश्यकता है।

तारकनाथ साहू, वरुणा अग्रवाल, सुदर्शन मैती (2023)[10] के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो 2015 में लॉन्च की गई थी, अपूर्णितों को बिना सुरक्षा के ऋण प्रदान करती है और वित्तीय संस्थाओं के साथ सहयोग करती है। डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस का उपयोग करते हुए, वर्तमान अध्ययन 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता की जांच करता है, विशेष रूप से, 2015-2016 से 2018-2019 तक छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करने में उनके प्रदर्शन को समझने के लिए। तीन श्रेणियों के तहत शिशु, किशोर और तरुण। अध्ययन में चार बैंक को तकनीकी रूप से कुशल माना गया है और अकुशल बैंकों में से चार बैंक मामूली रूप से अकुशल हैं। हालांकि परिणाम दिखाते हैं कि बैंकों ने मध्यम रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को फिर भी समान इनपुट मात्रा का उपयोग करके 1.2514 गुणा उत्पादन प्रदान करने का क्षमता है। इस योजना की सफलता वित्तीय संस्थाओं की क्षमता पर निर्भर करती है। कई व्यवसाय हाउसेज ऋण और अन्य सेवाओं के लिए बैंकों पर निर्भर करते हैं। नियमित दक्षता मापन त्रुटियों का पहले ही पता लगाने में मदद करेगा और समस्याओं के घटने की घटना को कम करने के लिए कदमों को लागू करने में मदद करेगा।

अनुग्रह रोहिणी लाल (2018)[11]केअनुसारबचत और निवेश संबंधित होते हैं। इस संदर्भ में में आय उत्पादन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोजगार के अवसर और आत्म-रोजगार का संचालन आय उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, नए व्यवसाय या छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए माइक्रो वित्त की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह पाया गया है कि अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र से ऋण लेते हैं। नवीनतम योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन आर्थिक परिवर्तन लाने में सहायक होगा। इसलिए, ऋण प्रदान करने और व्यवसायों को पुनर्वित्त करने के लिए 2015 में भारत सरकार द्वारा मुद्रा योजना शुरू की गई है, जो गैर-निगमित, गैर-कृषि छोटे/माइक्रोउद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए है। ये ऋण प्रधान मुद्रा लोन के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। योजना का प्रदर्शन अधिकांश मामलों में सफल रहा है, लेकिन आरंभिक चरण में बड़ा रुझान दिखाया गया है, जोक सालों के साथ धीमा हो गया है। प्रस्तावना में व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का विश्लेषण किया गया है। यह विश्लेषण दिखाता है कि लोग उद्यमिता को विकसित करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और अपना काम शुरू करने के लिए पहल कर रहे हैं। इससे प्रकट होता है कि मुद्रा योजना का प्रदर्शन किशोर और तरुण वर्गों में सफल है जबकि शिशु वर्ग कमजोर है, जिसके कारण कुल वित्त प्रसारण भी घट गया है। यह उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम बनाने में उपयोगी होगा।

पुष्पेंद्र कुमार और दिव्या नंद्राजोग (2021)[12] के अनुसार एक देश के पूर्णतावादी विकास को सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास के अलावा समाज के अन्य क्षेत्रों में आधारित माना जाता है। इसलिए, एक शक्तिशाली आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छे संरचित कार्यक्रम को रखा जाना चाहिए जो गरीबी को कम करने और लोगों को पूंजी के विभिन्न कारकों तक आसान पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। सरकारों ने घास की जड़ स्तर पर समस्याओं को निशाना बनाने और समाज की कमजोर वर्गों को उत्थानित करने के लिए योजनाबद्ध हस्तक्षेप किए हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम माइक्रोफाइनेंसिंग कार्यक्रम है जो हमारी युवा की ऊर्जा को उत्पादक गतिविधियों में अनुदान प्रदान करके उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके निर्मित करता है।

भारतीय सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसे मुद्रा योजना कहा जाता है जो महिलाओं के उत्थान और छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास से संबंधित है। इसलिए, हमारा वर्तमान अध्ययन भारत में मुद्रा योजना के सामाजिक और आर्थिक विकास पर प्रभाव की जांच करने का उद्देश्य रखता है। हमारे विश्लेषण के उद्देश्य के लिए प्राथमिक आंकड़े टेलीफोनिक साक्षात्कार के माध्यम से लगभग 300 महिला प्रतिस्पर्धियों से एकत्रित किए जाते हैं। डेटा के ग्राफिकल और टैबलेट विश्लेषण के परिणाम हमें बताते हैं कि मुद्रा ने हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक भूमिका निभाई है। मुद्रा ऋण ने महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाया है और उन्हें अपना व्यापार स्थापित करने में मदद की है। कई प्रतिस्पर्धियों ने ऋण लेने के बाद अपने मासिक घरेलू आय और बचत में वृद्धि की भी रिपोर्ट की है।

निष्कर्ष

उपरोक्त साहित्य के समीक्षात्मक अध्ययन से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का संचालन बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें "महिला उद्यमिता" को बढ़ावा दिया गया है। मुद्रा योजना के लाभार्थियों की संख्या देश भर में बढ़ रही है क्योंकि इसके तहत छोटे व्यवसायों, कमजोर आय समूहो, तथा छोटे स्तर पर काम को शुरुआत करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे नये रोजगारों का सृजन हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति हुई है। मुद्रा योजना के तहत बहुत कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है इसलिए आवेदक की प्रोफाइल को देखते हुए ब्याज दर पर लगाई जाती है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सुधारात्मक कार्य भी किए जाने चाहिए जैसे की एमएसएमई में आ रही वित्तीय समस्याओं का समाधान खोजा जाना चाहिए ताकि मुद्रा योजना का और भी बेहतर डिजाइन हो सके और युवा आबादी को ज्यादा से ज्यादा उद्यमी बनाया जा सके। जिसके तहत लोग वित्तीय रूप से शक्तिशाली होंगे और इस योजना के वास्तविक उद्देश्य को भी तभी हासिल किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आ रही सभी समस्याओं के हल होने से एक सौ प्रतिशत रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप सभी लोग अपनी इच्छा के अनुरूप रोजगार लेने में समर्थ होंगे और तभी आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. दीक्षित, राधिका, घोष, मुनमुन, " फाइनेंशियल इंक्लूजन फोर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ़ इंडिया - ए स्टडी ऑफ़ इंडियन स्टेट" , इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ बिज़नस मैनेजमेंट एंड रिसर्च (आईजेबीएमआर), आईएसएसएन 2249- 6920, वॉल्यूम - 3, इशू -1, (मार्च, 2013), पृष्ठ 147 – 156
2. रूपा, आर., " प्रोग्रेस ऑफ़ मुद्रा विद स्पेशल रेफरेंस टू तमिलनाडु" , इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इकोनामिक एंड बिजनेस रिव्यू, आईएसएसएन 2347-9671, वॉल्यूम-5, इश्यू-1, (जनवरी, 2017) 8028
3. जॉर्ज, बी एंड नलिनी, जे, "रोल ऑफ़ मुद्रा बैंक इन द ग्रोथ ऑफ़ एमएसएमई।" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ बिजनेस एंड मैनेजमेंट इन्वेंशन (आईजेबीएमआई), आईएसएसएन 2319-, वॉल्यूम 7, संख्या (2), (फरवरी, 2018), पृष्ठ 59-62
4. सिंह, रोशन, बिंदल, अनीता, "ग्रोथ ऑफ़ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) इन हरियाणा स्टेट", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इन्नोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लोरिंग इंजीनियरिंग (आईजेआईटीईई), आईएसएसएन- 2278-3075, वॉल्यूम - 8, ईशु - 12, (अक्टूबर, 2019)
5. बिंदल, अनीता, सिंह, रोशन, "ए स्टडी एंड रिव्यु ऑफ़ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना", जर्नल ऑफ़ एजुकेशन : रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, आईएसएसएन - 0972-7175, वॉल्यूम - 23, संख्या -1, 2022,
6. एस., बी., शशांक, मय्या, सुरेशरमण, "एन एनालिसिस ऑफ़ पैन-इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएसन अकांप्लिश्ड थ्रो द इंप्लीमेंटेशन ऑफ़ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)- लिटरेचर रिव्यू" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ केस स्टडीज इन बिजनेस, आईटी एंड एजुकेशन (आईजेसीएसबीई), आईएसएसएन - 2581-6942, वॉल्यूम - 6, संख्या - 2, (अगस्त, 2022)
7. एल., एच.,अंजेश, " ए स्टडी ऑन अवेयरनेस लेवल ऑफ़ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इन शिवमोग्गा डिस्टरिक कर्नाटक" पीआईएमटी जर्नल ऑफ़ रिसर्च, आईएसएसएन - 2278 - 7925, संख्या - 3, (अप्रैल, 2021)
8. महाजन, डी, योगेश, " ए स्टडी एंड रिव्यू ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) इन द स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एडवांस एंड इन्नोवेटिव रिसर्च, ई-आईएसएसएन - 23947780, वॉल्यूम - 6, ईशु - 2, (अप्रैल - जून, 2019)
9. कुमार, अजीत, रानी, पूनम, "परफॉर्मेंस आॉफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई): ए केस स्टडी ऑफ़ हरियाणा", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन सोशलसाइंस, आईएसएसएन - 2249-2496, वॉल्यूम-9, इशू-5, (2019), पृष्ठ 693-709
10. साहू, तारकनाथ, अग्रवाल, वरुणा, मैती, सुदर्शन, " सोशल वेलफेयर थ्रो मुद्रा योजना: हाउ डिड द पब्लिक सेक्टर बैंक्स परफॉर्म इन रिलाइजिंग दि ड्रीम?", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ बिज़नस एक्सीलेंस, (आईजेबीईएक्स), वॉल्यूम - 31, संख्या - 3, (पब्लिश्ड 14 नवंबर, 2023), पृष्ठ 450 – 467
11. लाल, रोहिणी, अनुग्रह, "ए स्टडी ऑन क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ़ मुद्रा योजना इन उत्तराखंड", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंस एंड इकोनामिक रिसर्च, आईएसएसएन 2455 - 8834, वॉल्यूम - 3, इश्यू - 7, (जुलाई, 2018)
12. कुमार, पुष्पेंद्र नंद्राजोग, दिव्या, "द इंपैक्ट ऑफ़ प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाऑफ़ द सोशियो इकोनामिक डेवलपमेंट ऑफ़ वूमेन इन इंडिया : ए स्टडी ऑफ़ दिल्ली एनसीआर", एशियन जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट, डेट ऑफ़ एक्सेप्टेड (31 मई, 2021), डीओआई: 10.52711/2321-5763.2021.00062